



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]
No. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1990/माघ 2, 1911
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1990/MAGHA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

श्रम मंत्रालय

समाचार-पत्र स्थापनों और समाचार-पत्र एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी कर्मचारियों की बाबत मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारत्मक भत्ता की पुनरीक्षित दरों की सिफारिशों में उपंतरण।

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1990

का.अ. 71(अ). श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारियों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या उनका पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13 ग के अधीन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.अ. 527(अ) और 528(अ) द्वारा जो दोनों, तारीख 17 जुलाई, 1985 की है, दो मजदूरी बोर्ड गठित किए थे;

और पूर्वोक्त मजदूरी बोर्डों ने 30 मई, 1989 को अपनी सिफारिशों केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दीं;

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 1989 के राजपत्र, असाधारण में का.अ. 684(अ) के रूप में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे अनुसूची में उल्लेखित मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारत्मक भत्ता के संदाय के संबंध में अपनी रिपोर्ट के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) में और अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12 (क) और 12(ख) में अस्तित्वित उक्त मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों में कुछ उपंतरण करने का प्रस्ताव किया था;

और उक्त सिफारिशों पर विचार किया गया और उक्त सिफारिशों में कुछ ऐसे उपंतरण करना सरकार ने ठीक समझा जो सरकार को राज्य में सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जिनके प्रस्तावित उपंतरणों से प्रभावित होने की संभावना थी, सूचनाएं जारी की गई थीं और इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए बोर्डों की सिफारिशों

के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) या अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12(क) और 12(ख) में निम्नलिखित उल्लेख है, अर्थात्:

(1) अमजीबी पत्रकारों और गैर-अमजीबी समाचार-पत्र कर्मचारियों बोर्ड की गिकारियों के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में मांगी 3 के स्थान पर निम्नलिखित मांगी रखी जाएगी, अर्थात्:

"मांगी 3

मकान किराया भत्ता की दरें

(क्षेत्र का प्रतिशत)

समाचार-पत्र का स्थापन का वर्ष	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

टिप्पण: उपरोक्त वर्णित मकान-किराया भत्ता की दरें किसी नगर में किसी वर्ग के समाचार-पत्र स्थापन के अधीन कर्मचारियों के किसी समूह के लिए अधिकतम 1200/- रु. होंगी।

(2) अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकार्यक भत्ता के संबंध में मांगी 4 के स्थान पर निम्नलिखित मांगी रखी जाएगी, अर्थात्:

"मांगी 4

नगर प्रतिकार्यक भत्ता

(प्रतिमास दरें)

स्थापन का वर्ष	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	रु. 100	रु. 75	रु. 20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20";

(3) अमजीबी पत्रकारों और गैर-अमजीबी समाचार-पत्र कर्मचारियों बोर्ड की गिकारियों के अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में मांगी 3 के स्थान पर निम्नलिखित मांगी रखी जाएगी, अर्थात्:

"मांगी 3

मकान किराया भत्ता की दरें

(क्षेत्र का प्रतिशत)

समाचार पत्र एजेंसी का वर्ष	20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	15	14	13
II	15	14	13

टिप्पण: पूर्वोक्त वर्णित मकान किराया भत्ता की दरें किसी नगर में समाचार एजेंसी के किसी समूह के लिए अधिकतम 1200/- रु. होंगी।

(4) अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकार्यक भत्ता के संबंध में मांगी 4 के स्थान पर निम्नलिखित मांगी रखी जाएगी, अर्थात्:

"मांगी 4

नगर प्रतिकार्यक भत्ता की दरें

(प्रतिमास दरें)

स्थापन का वर्ष	20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	रु. 100	रु. 75	रु. 20
II	75	50	20";

यं गिकारियों उपरोक्त उपांतरण के अधीन रहते हुए आदेश की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

अनुसूची

सूचक बोर्डों की रिपोर्टों के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) और अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12(क) और 12(ख) में दलविष्ट गिकारियों।

अध्याय 3

भाग 1

धमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों से भिन्न समाचार कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की मिकारिमें

(समाचार एजेंसियों में भिन्न समाचार स्थापनों के कर्मचारियों के लिए)

खण्ड 5

अन्य भत्ते :

19(क) मकान किराया भत्ता—इसमें संलग्न सारणी III में उपदर्शित रूप में मकान किराया भत्ता भी उसमें वर्णित समाचारपत्र स्थापनों द्वारा संबंधित जोन में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

परन्तु यह कि :—

- (1) जहाँ किसी कर्मचारी के लिए समाचारपत्र स्थापित द्वारा नियाम स्थान की व्यवस्था की गई है वहाँ कोई मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा,
- (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता संदेय किया जा रहा है तो वह इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते की रकम के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा,
- (3) जहाँ कोई समाचारपत्र स्थापन किसी कर्मचारी को अपने निवास स्थान का स्वामी होने के लिए कर्मचारी को समर्थ बनाने के लिए किसी निधि में किसी रकम का अभिदाय करता है तो ऐसी रकम को इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(ख) नगर प्रतिकरात्मक भत्ता—इसमें संलग्न सारणी 1 में उपदर्शित रूप में नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उसमें उपबर्णित समाचारपत्र स्थापनों द्वारा संबंधित जोनों में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

सारणी 3

मकान किराया भत्ते की दरें

दरें

समाचार पत्र

स्थापन

का वर्ग

'क'

'ख'

'ग'

नगर/कस्बे, जिनकी जन-संख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है

नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है

नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है

1	2	3	4
I. वेतन का 11 प्रतिशत अधिकतम 330 रुपए	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 300 रुपए	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए	
II. वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 300 रुपए	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए	
III. वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए	

III. वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए
IV. वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपए
V. वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपए	वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम 120 रुपए

सारणी-4

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

(दर प्रति मास)

जोन	'क'	'ख'
समाचारपत्र स्थापन का वर्ग	नगर, कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है
I	80 रुपए	20 रुपए
II	65 रुपए	20 रुपए
III	50 रुपए	20 रुपए
IV	35 रुपए	20 रुपए
V	30 रुपए	20 रुपए

भाग—II

समाचार एजेंसियों के लिए धमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की मिकारिमें

खण्ड-5

अन्य भत्ते :

12(क). मकान किराया भत्ता :

इसमें संलग्न सारणी III में उपदर्शित रूप में मकान किराया भत्ता भी उसमें वर्णित समाचारपत्र एजेंसियों द्वारा संबंधित जोनों में तैनात किए गए अपने कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा। परन्तु यह कि (1) जहाँ किसी कर्मचारी के लिए समाचार एजेंसी द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था की गई है वहाँ कोई मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा, (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता संदेय मकान किराया भत्ते की रकम के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, (3) जहाँ कोई समाचार एजेंसी किसी कर्मचारी को और से अपने निवास स्थान का स्वामी होने के लिए कर्मचारी को समर्थ बनाने के लिए किसी निधि में किसी रकम का अभिदाय करता है तो ऐसी रकम को इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(ख) नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :—इसमें संलग्न सारणी 4 में दर्शित रूप में नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उसमें उपदर्शित समाचार एजेंसियों द्वारा संबंधित जोनों में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

सारणी 3

सकल किराया भत्ता

(दर प्रति मास)

समानाचार पत्रकारियों का वर्ग	"क"	"ख"	"ग"
	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है।	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है।	नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है।
वर्ग I और II	बैतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 500 रुपए	बैतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 400 रुपए	बैतन का 7½ प्रतिशत और अधिकतम 350 रुपए

घाटा 12 के अर्थात् केन्द्रीय सरकार की विकासियों को प्रभावित बनाने वाले अर्थों की लागत का विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में विकासियों में सुधार किया जाता है। यदि यह प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यह दोनों में से कोई भी उससे अधिक है जिसकी हमें शिकायत की गई है।

सारणी 4

नगर प्रचारिकात्मक भत्ता

(दर प्रति मास)

समानाचार पत्रकारियों का वर्ग	"क"	"ख"
	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है।	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है।

I	50 रुपए	20 रुपए
II	35 रुपए	20 रुपए

[स. एत. 33014/1/89-इन्फ. बी.]

प्रधान सचिव, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

MODIFICATION IN THE RECOMMENDATIONS OF REVISED RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE AND CITY COMPENSATORY ALLOWANCE IN RESPECT OF WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES OF NEWSPAPER ESTABLISHMENTS AND NEWS AGENCIES

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 1990

S.O. 71 (E):—Whereas for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the Central Government constituted two Wage Boards under Section 9 and Section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions

Act, 1955 (45 of 1955) by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. SO 527 (E) and 528 (E) both dated 17th July, 1985;

And whereas, the aforesaid Wage Boards submitted their recommendations to the Central Government on the 30th day of May, 1989;

And whereas the Central Government by its Order published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st August, 1989 as SO. 684(1) inter-alia proposed to make certain modifications in the recommendations of the said Wage Boards contained in paragraphs 19(a) and 19(b) of Section V of Part I under Chapter IX and paragraphs 12(a) and 12(b) of Section V of Part II under Chapter IX of their Report in relation to payments of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance appended in the Schedule below;

And whereas the said recommendations were examined and Government deemed it fit to make certain modifications in the said recommendations, which in the opinion of the Government, would effect important alterations in the character of the recommendations;

And whereas in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 12 of the said Act, notices were issued to the persons likely to be affected by the proposed modifications and whereas representations received in this behalf have been taken into account;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the said Act, the Central Government makes the following modifications to paragraphs 19(a) and 19(b) of Section V of Part I under Chapter IX paragraphs 12(a) and 12(b) of section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist newspaper employees, namely:—

(i) for Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE III
Rates of House Rent Allowance (Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment.	Cities/Towns with Population of 20 lakhs and above	Cities/Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with population less than 10 lakhs
IA	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

Note.—The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city.

(ii) for Table IV in relation to City Compensatory Allowance, under Section V of Part I under Chapter IX the following table shall be substituted, namely:

TABLE IV

City Compensatory Allowance (Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more
	Rs.	Rs.	Rs.
IA	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20";

(iii) for Table III, in relation to the House Rent Allowance under Section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted, namely :

TABLE III

Rates of House Rent Allowance (Percentage of Pay)

Class of News Agency	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of less than 10 lakhs
I	15	14	13
II	15	14	13

Note:—The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of News Agency in any City";

(iv) for Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part II under Chapter IX, the following Table shall be substituted, namely :

TABLE IV

Rates of City Compensatory Allowance (Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more
	Rs.	Rs.	Rs.
I	100	75	20
II	75	50	20";

These recommendations subject to the above modification shall come into force on the date of this Order.

192 GT/90—2

SCHEDULE

Recommendations contained in paragraph 19(a) and 19(b) of section V of Part I under Chapter IX and paragraph 12(a) and 12(b) of Section V of Part II under Chapter IX of the Reports of the Wage Boards.

CHAPTER—IX

PART—I

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARD FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

(For employees of Newspaper Establishments other than News Agencies)

SECTION—V

Other Allowances :

19(a) House Rent Allowance.—House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones, provided that:—

- (1) Where an employee is provided residential accommodation by Newspaper Establishment, no House Rent Allowance will be payable.
- (2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision.
- (3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) City Compensatory Allowance.—City Compensatory Allowance as indicated in Table IV attached herewith will be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones.

TABLE III

RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE
RATES

Class of Newspaper Establishment	'A'	'B'	'C'
	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census	Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per latest census
(1)	(2)	(3)	(4)
IA	11% of pay Max. Rs. 330	10% of pay Max. Rs. 300	9% of pay Max. Rs. 270
I	10% of pay Max. Rs. 300	9% of pay Max. Rs. 270	8% of pay Max. Rs. 240
II	9% of pay Max. Rs. 270	8% of pay Max. Rs. 240	7% of pay Max. Rs. 21
III	8% of pay Max. Rs. 240	7% of pay Max. of Rs. 210	6% of pay Max. Rs. 180
IV	7% of pay Max. Rs. 210	6% of pay Max. Rs. 180	5% of pay Max. Rs. 150
V	6% of pay Max. Rs. 180	5% of pay Max. Rs. 150	4% of pay Max. Rs. 120

TABLE IV
CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensem)

Zone	'A'	'B'
Class of News- paper Establish- ment	Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census
IA	Rs. 80	Rs. 20
I	Rs. 65	Rs. 20
II	Rs. 50	Rs. 20
III	Rs. 35	Rs. 20
IV	Rs. 30	Rs. 20
V	Rs. 30	Rs. 20

PART II

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARDS FOR WORKING JOURNALISTS & NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES FOR NEWS AGENCIES

SECTION V

Other Allowances:

12(a) House Rent Allowance:

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by News Agencies mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a News Agency, no House Rent Allowance will be payable, (2) if an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision, (3) where a News Agency contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) City Compensatory allowance:

City Compensatory allowance as shown in Table IV attached herewith will be paid by the News Agencies indicated therein to the employees posted in the respective zones.

TABLE III

HOUSE RENT ALLOWANCE

(Rates per mensem)

	'A'	'B'	'C'
Class of Cities/Towns News Agencies with a population of 20 lakhs and above as per census of 1981	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1981	Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1981	
Classes I and II	15% of pay subject to a maximum of Rs. 500/-	10% of pay subject to a maximum of Rs. 400/-	7½% of pay subject to a maximum of Rs. 350/-

In respect of employees existing on the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations, the recommendation will not affect the quantum or rates of HRA if either are higher than what is recommended herein.

TABLE IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensem)

	A	B
Class of Cities/Towns News Agencies with a population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census	
I	Rs. 50	Rs. 20
II	Rs. 35	Rs. 20

[No. S-33014/1/89—WB]

PADMA VENKATACHALAM, Dy. Secy.